(iii) SETTLEMENT OF CAUVERI WATER DISPUTE BETWEEN TAMIL NADU, KARNATAKA AND KERALA

SHRI K. RAMAMURTHY (Krishnagiri): It will be no exaggeration to say that the soul of Tamilnadu is the water from the river Cauvery. If the water from Cauvery is stopped for one agricultural season, the entire Tamil Nadu will become arid zone. The granary of Tamil Nadu, that is to say the Cauvery Delta in Tamil Nadu, will become the graveyard for the people of Tamil Nadu.

It is unfortunate that the 1924 Cauvery Water Agreement between Karnataka and Tamil Nadu has become a matter of political dispute between these two States. The Government of India has also been repeatedly assuring the people of Tamil Nadu that Cauvery Valley authority would be set up. This assurance is yet to become a reality.

Many rounds of talks have been held between the Chief Ministers of Tamil Nadu and Karnataka. Recently, it is understood that the Government of Karnataka is building a dam even without the express sanction of the Central Planning Commission, which would mean that there would be drastic decline in the supply of Cauvery water to Tamil Nadu.

Besides, this, the Government of Karnataka is also objecting to the construction of Hogenekal Thermal Power Project in Tamil Nadu. This causes avoidable problems for Tamil Nadu which is afflicted by recurring power cuts on account of which the wheels of industries have come to a grinding halt.

The Central Government should immediately call a meeting of the Chief Ministers of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala and the dispute of decades should be resolved forthwith in order to ensure that the lives of 4.5 crore people of Tamil Nadu are not jeopardised.

(iv) PAY PARITY OF HOME GUARDS WITH POLICE CONSTABLES

SHRI MUKANDA MANDAL: (Mathurapur): Home guards throughout the country who are the most neglected lot in spite of the fact that this force was formed with a historical background. They are supposed to be the auxiliary to the police and generally help in maintaining internal security, but they have to work as much as the Constables do. Apart from this work, their role is to help the community in any kind of emergency, an air raid, a fire, a flood, an epidemic, an earthquake, a cyclone and so on. They are to participate in socio-economic and welfare activities such as adult education, health and hygiene, development schemes and such other tasks as are deemed to promote communal harmony and give assistance to the administration in protecting weaker sections of the society. There are about five lakhs of Home Guards throughout the country, but it is unfortunate that they are poorly paid and their service depends on the whims and fancies of some police officers. They are virtually treated like slaves by their superiors.

In view of the recent judgement of the Supreme Court that the right to "equal pay for equal work" is a fundamental right and enforceable as such, I urge upon the Hon. Home Minister to look into this matter seriously and release necessary funds and recommendation so that their pay and service conditions are brought on par with that of Constables.

(v) INDISCRIMINATE SPENDING OF MONEY BY GOVERNMENT DEPARTMENTS DURING THE MONTH OF MARCH

**प्रो० अजित कुमार मेहता** (समस्तीपुर) : मार्च के अन्त में किये गये अनाप शनाप खर्च के बारे में प्रति वर्ष लेखा परीक्षा विभाग और अन्य प्रशासकीय विभाग गम्भीर आपत्तियां उठाकर अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं । फिर भी अब तक कोई ठोस सुधार नजर नहीं आया है । लोक निर्माण, सिंचाई, गृह निर्माण, विद्युत प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि बड़े विभागों में 31 मार्च को मेला लगा रहता है ।

[श्री अर्जुन कुमार सेठी]

खर्च के इस महापर्व के दिन महीनों चलने वाली सरकारी कार्यालयों में क्रय करने की जटिल प्रक्रिया कुछ घंटों में ही पूरी कर ली जाती है। इससे केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ही नहीं होता, बल्कि वित्तीय अनुशासन में भी शिथिलता आ जाती हैं। अनेक प्रकरणों में अनियमित भुगतान हो जाते हैं तथा भीड़ के कारण इस आपाधापी में गबन की घटनाएं भी घट जाती हैं।

बजट पारित होने के बाद धनराशि का आबंटन छोटे-छोटे कार्यालयों तक काफी देर से पहुंचता है। तब तक मानसून आ जाने के कारण कई योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पाती। बजट प्रावधान समय पर मिल भी जाये, तो भी पुनर्नियोजन के कारण वित्तीय वर्ष के लगभग अन्त में ही कार्यालयों को खर्च के लिये धनराशि प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में योजनाबद्ध रूप से धन व्यय नहीं हो पाता। व्यवस्था इस प्रकार की हो कि कर्मचारियों को किसी एक दिन देर रात तक दफ्तर खुला रख कर भुगतान का सिलसिला जारी रखने की विवशता न हो। वर्ष के अन्त में भारी धनराशि तथा अनियमित व्यय की तुलना में धन की वापसी को प्रोत्साहित किया जाना, किसी भी दृष्टि से गलत नहीं होगा। दावों के भुगतान संबंधी नियमों में भी कुछ ऐसे उदार संशोधन किये जाने चाहिये, जिससे वर्ष के अन्त में उनके भुगतान की अनिवार्यता न रहे और शेष बचे दावों के भुगतान के लिये आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में उपयुक्त प्रावधान हो सके।

(vi) IRRIGATION FACILITIES FOR CHOTANAGPUR AREA.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति जी, जो मैंने नियम 377 के अन्तर्गत अपना वक्तव्य दिया था उसमें इतना संशोधन कर दिया गया है कि उसे अब मैं पढ़ना उचित नहीं समझता हूं। छोटा नागपुर में अपरसकरी जलाशय योजना और तिलैया डैम डाईवर्शन योजना अगर बनती है तो उस क्षेत्र से लोगों का बहुत बड़ा अहित होगा। इनसे बीस हजार एकड़ जमीन डूब जायेगी, 60 गांव डूब जायेंगे और 150 ट्यूबवेल्स डूब जायेंग। यह योजना वहां की जनता के लिए बड़ी अहितकर हैं और वहां की जनता की आकांक्षाओं के प्रतिकूल हैं। इसलिये मैं इस वक्तव्य को नहीं पढ़ना हूं।**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत जो हम नोटिस देते हैं उनको संशोधित करने में उनकी मूल भावना को बदला जाता है। जब हमारे नोटिस की भावना को बदला जाता है उस वक्त कम से कम सम्बन्धित मेम्बर को कांफिडेंस में तो लेना चाहिये। एक तो आप के स्टाफ में हिन्दी जानने वाले कम हैं। हम हिन्दी में जो भाव व्यक्त करते हैं उसको अंग्रेजी में करके फिर उसे काट छांटा जाता है। इससे जिस उद्देश्य से हम नियम 377 के अन्तर्गत अपना नोटिस देते हैं उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। आपके सेक्रेटेरियेट को चाहिये कि जब भी वह हमारे नोटिस में काट-छांट करे तो हमें कांफिडेंस में लेवे और बतावे कि इस तरह की बात हम इसमें नहीं रखना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN: I will bring it to the notice of the Speaker.

(vii) DIRECTIONS TO STATE GOVERNMENTS OF UTTAR PRADESH AND RAJASTHAN TO SUPPLY POWER TO FARMERS.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): The power supply to the farmers in Western U.P. and Rajasthan is hardly for 4 to 5 hours a day. This supply

**Text not complete.